छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या का घटना

*526. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस घटत की दर क्या है तथा इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे और सीमांत किसानों की संख्या घटने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन छोटे और सीमांत किसानों को भूमिहीन होने से बचाने हेतु सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशिष्ट घटकों पर विशेष रियायतों/राजसहायता के साथ अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें छिड़काव और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों पर राजसहायता/रियायतें, उन्नत फार्म उपकरणों, फसल बीमा, ऋण, भूमि समतलन और भूमि जल विकास शामिल हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के गठन से भी छोटे और सीमान्त किसानों के लिए आय और रोजगार के सृजन में सहायता मिलेगी।

उर्वरक, प्रौद्योगिकी, विस्तार, ऋण, मूल्य निर्धारण, अधिप्राप्ति, फसल कटाई पश्चात के प्रबन्धन, व्यापार, अवसंरचना आदि के संबंध में ये योजनागत राजसहायता/रियायतें तथा विभिन्न नीतिगत उपाय छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से लागू किए गए हैं।

Payment of Taxes of ATF

*527. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the names of the foreign companies which are not making payment of sales tax and other State taxes on Aviation Turbine Fuel (ATF) to various oil companies as on 31st March, 1998;

(b) the amount of arrears outstanding against each airline; and

(c) the steps taken to ensure the recovery?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) and (b) The names of the foreign airlines which are not making payment of sales tax on ATF to the oil companies and the amounts outstanding against each airline as on 31.3.98 is given in the Statement. (*see* below)

(c) The International airlines have represented that they are not liable to pay sales-tax as the Air Services Agreement signed by India with foreign countries specifically stipulates that airlines of the two sides shall be exempt from all national duties and levies on fuel on reciprocal basis. To resolve this issue, this matter has been considered at various levels. Oil Companies have also been constantly contacting these airlines for making payment of the dues.

Statement

List of Foreign Airlines not paying Sales Tax & amounts involved as on 31.3.98 (Provisional)

(Rs. Lacs)

	IOC	BPCL	HPCL	TOTAL
Singapore Airlines	428.87	107.32		536.19
Lufthansa German Airlines	4043.04			4043.04
Kuwait Airways	555.95			555.95
Saudi Arabian Airlines	1012.21			1012.21
El Al Israel	679.33			679.33
Royal Jordanina Airlines	557.05			557.05
Syrian Arab Airlines	49.78			49.78
Cathay Pacific Airways	252.22			252.22
Aeroflot Soviet Airlines	236.28		32.75	269.03

	IOC	BPCL	HPCL	
Yemenia Yemen Airways	52.46			52.46
Thai Airways	275.00			275.00
Air France	1552.00			1552.00
Scandinavian Airlines System	199.00			199.00
United Airlines	489.00			489.00
Turkemenistan Airlines	12.00			12.00
Austrian Airlines	16.00			16.00
North West Airlines	54.00	160.89		214.89
Malaysian Airlines	88.20			88.20
British Airways	231.20	3463.71		3694.91
Swiss Air	124.25	2255.87		2380.12
KLM Royal Dutch	160.68	1699.14		1859.82
Gulf Airways	52.96	141.75		194.71
Alitalia		855.54		855.54
Korean Air		195.84		195.84
Uzbekistan Airways		147.91		147.91
Air Mauritius		200.67		200.67
Kenya Airways		126.17	117.17	243.34
Delta Airlines		48.33	949.42	997.75
Egypt Air		92.32		92.32
All Nippon Airlines		116.83		116.83
Air Canada		224.79		224.79
Emirates		111.67		111.67
Martin Air		0.62		0.62
Japan Airlines		50.32		50.32
Asiana Airlines		15.87		15.87
Bellview Airlines		12.40		12.40
				0.00
				0.00
TOTAL:	11121.48	10027.96	1099.34	22248.78

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

***528. श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के बीच चल रहे विवादों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मणिपुर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने हेतु सरकार ने कोई विशेष प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और राज्य के कितने जिलों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है?